

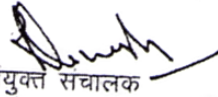
प्रश्न सं. [क. 517]

परिशिष्ट- "अ"

विधानसभा अताराकित प्रश्न क्रमांक 517 - गाननीय विधायक श्रीइंजीनियर प्रदीप लारिया

1. म.प्र. जनभागीदारीयोजनान्तर्गत वित्त विभाग म.प्र. शासन की अधिसूचना 2000 के पैरा क्रमांक- 7 में निर्देश दिये गये हैं कि मुख्यतः ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों की मूलभूत सेवाओं से सम्बन्धित योजनाएँ ली जायेंगी। अथवा ऐसी योजनाएँ जो ग्रामवासियों के लिये जनोपयोगी हैं। ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये, जिनमें गरीब तबके/अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ हो। सम्मिलित की जावे।

2- म.प्र. शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल का पत्र क्र० 68/316/07/23/योआसा./भोपाल, दिनांक 11.01.2008 द्वारा जनभागीदारी नियम 2000 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत में अगर अजा./अजजा. वार्ड है और वहाँ मतदाताओं की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो वहाँ पर 75 प्रतिशत शासन अंशदान राशि की स्वीकृत दी जा सकती है।


संयुक्त संचालक
सभागीय योजना एवं सांख्यिकी
सागर